

लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र (राबर्टसगंज, अनपरा, शक्तिनगर), सिंगरौली, मिर्जापुर, अयोध्या, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़ से प्रसारित

E-mail : dainikdevvrat@gmail.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

1

लोकसभा की 170 सीटों के टारगेटेड परिशीमन से किसका होगा भला

नई दिल्ली, 12 जून (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। देश में आगामी महीनों में होने वाले परिशीमन (कमसंपन्नपुनर्जापवद) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण सुझाव सामने आया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के एक वरिष्ठ पत्र में सुझाव दिया गया है कि भारत को देश की सभी लोकसभा सीटों पर एक समान नियम लागू करने के बजाय एक लक्षित मानदंड (targeted criterion) अपनाया जाए। इसके तहत देश के 170 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे निचले सदन (लोकसभा) की कुल सदस्य संख्या 543 से बढ़कर 824 हो जाएगी। लेकिन लोकसभा की 824 सीटों से किसका भला होने जा रहा है। यह विश्लेषण इस रिपोर्ट के अंत में पढ़ने को मिलेगा। पहले जानिए कि सरकार को सुझाव क्या दिया गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के मुदित कपूर ने इस पत्र को तैयार किया है। इस वरिष्ठ पत्र में सीटों को बांटने का एक स्पष्ट फॉर्मूला सुझाया गया है।

59 निर्वाचन क्षेत्रों को दो भागों (Two-way split) में विभाजित किया जाए। 111 निर्वाचन क्षेत्रों को तीन भागों (Three-way split) में विभाजित किया जाए। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस टारगेटेड परिशीमन के कारण अगले आम चुनाव में मतदाताओं के मतदान (voter turnout) में 0.3 से 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में लगभग 90 लाख से लेकर 2.3 करोड़ तक अतिरिक्त मतदाता अपने मतदाताओं का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। इस मॉडल के अनुसार, सीटों के विभाजन का असर देश के विभिन्न राज्यों पर इस प्रकार पड़ेगा। दो-तरफा विभाजन (Two-way split) - प्रस्तावित 59 सीटों में से 22 सीटें अकेले केरल और तमिलनाडु राज्यों से होंगी। तीन-तरफा विभाजन (Three-way split) - इसमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश (17 सीटें) का होगा। इसके बाद महाराष्ट्र (12 सीटें), बिहार (10 सीटें) और पश्चिम बंगाल (10 सीटें) का नंबर आता है। संशोधन के बाद राज्यों में सीटों की नई स्थिति। दक्षिण भारत-तेलंगाना में सीटें 17

से बढ़कर 26, आंध्र प्रदेश में 25 से 38, कर्नाटक में 28 से 42, तमिलनाडु में 39 से 59 और केरल में 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। उत्तर और पश्चिम भारत-महाराष्ट्र में सीटें 48 से बढ़कर 72, राजस्थान में 25 से 38, उत्तर प्रदेश में 80 से 120, मध्य प्रदेश में 29 से 44, गुजरात में 26 से 39 और बिहार में 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी। पीएम कमेटी रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इस नए फॉर्मूले को लागू करने के बाद भी संसद में दक्षिणी राज्यों और अधिक आबादी वाले उत्तरी व पश्चिमी राज्यों की कुल सीटों की हिस्सेदारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। दक्षिण भारत की हिस्सेदारी वर्तमान के 23.6% के मुकाबले 23.7% रहेगी, जबकि उत्तर और पश्चिमी राज्यों की हिस्सेदारी 45.2% से मामूली बदलकर 45.6% होगी। इससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर उठने वाले विवादों को शांत करने में मदद

मिलेगी। वरिष्ठ पत्र में इस बात पर चिंता जताई गई है कि देश में लोकसभा क्षेत्रों का आकार लगातार बढ़ रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार, एक औसत (उमकपद) लोकसभा क्षेत्र में 18.2 लाख पंजीकृत मतदाता थे। देश के कुछ सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में तो मतदाताओं की संख्या 32 लाख से भी अधिक हो चुकी है। इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के कारण मतदाताओं का वोट बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे अलग-अलग समूहों की भागीदारी असमान हो जाती है और प्रतिनिधित्व का अंतर (representation gap) गहरा जाता है। दावा है कि इस फॉर्मूले को इसी विवाद को सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके व्यावहारिक नतीजे उत्तर भारत के पक्ष में झुक सकते हैं। कागज पर संतुलन-वरिष्ठ पत्र के अनुसार,

यदि देश की 170 बड़ी सीटों को ही बांटा जाता है, तो दक्षिण भारत की लोकसभा में कुल हिस्सेदारी वर्तमान के 23.6% से मामूली बढ़कर 23.7% हो जाएगी। वहीं उत्तर और पश्चिमी राज्यों की हिस्सेदारी 45.2% से सिर्फ 45.6% होगी। यानी अनुपात में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। सीटों की संख्या का वास्तविक अंतर - भले ही प्रतिशत में अंतर न दिखे, लेकिन संसद के भीतर 'वोटों की शुद्ध संख्या' (Absolute Number) में उत्तर भारत का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की मौजूदा 80 सीटें बढ़कर 120 हो जाएगी। उसे 40 सीटों का फायदा होगा। बिहार की मौजूदा 40 सीटें बढ़कर 60 हो जाएगी। उसे 20 सीटों का फायदा होगा। तमिलनाडु की मौजूदा 39 सीटें बढ़कर 59 हो जाएगी। उसे 20 सीटों का फायदा है। केरल की मौजूदा 20 सीटें बढ़कर 30 हो जाएगी। उसे 10 सीटों का फायदा होगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा: नकारात्मक प्रभाव-अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर 60 नई सीटें मिल रही हैं, जबकि पूरे तमिलनाडु और केरल को मिलाकर सिर्फ 30 नई

सीटें मिलेंगी। संसद में कोई भी बिल पास कराने या सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या मायने रखती है, प्रतिशत नहीं। ऐसे में उत्तर भारत के राज्यों का राजनीतिक वजन स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ जाएगा। इससे देश के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 824 करने का मतलब है 281 नए सांसदों का जुड़ना। इसके कारण होने वाले खर्चों को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। सांसदों का प्रत्यक्ष खर्च-प्रत्येक नए सांसद को वेतन, भत्ते, मुफ्त यात्रा, चिकित्सा सुविधाएं, दिल्ली में सरकारी आवास और पेंशन देनी होगी। MPLAD फंड का बोझ-वर्तमान में हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल '5 करोड़ का सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) फंड मिलता है। 281 नए सांसदों का मतलब है कि सरकार को केवल इस फंड के लिए हर साल 1,405 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे। प्रशासनिक खर्च- नई सीटों के लिए नए चुनाव कार्यालय, अतिरिक्त सुरक्षा बल, चुनाव कराने का खर्च और परिशीमन आयोग का अपना प्रशासनिक खर्च भी अरबों रुपये में होगा।

बंगाल में 4000 EVM के साथ सबूत भी आग में जलकर स्वाहा

राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा साजिश की आ रही बू



कोलकाता, 12 जून (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। पश्चिम बंगाल में 12 जून को हुए चुनाव के बाद नौ मंजिला सरकारी भवन में बुधवार को लगी। इस इमारत में साउथ 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी है। यह क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का मजबूत क्षेत्र रहा था। आग लगने की यह घटना चुनाव के बाद मंडल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। विपक्षी पार्टियाँ पहले से ही मंडल पर सवाल उठाती रही हैं, ऐसे में इस आग की घटना राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गई है। अभी तक किसी भी संगठन या व्यक्ति ने इस आग की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस की जांच से आगे की सच्चाई सामने आने की संभावना है। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है जबकि टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी चुनाव होने से पहले से ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही थीं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया और नतीजों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बीजेपी को भारी बहुमत मिलने के बावजूद ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और दावा किया कि शहम हारे नहीं हैं, 100+ सीटें लूटी गई हैं। एसआईआर के दौरान करीब 90 लाख नाम वोट लिस्ट से हटाए गए। ममता ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया मनमानी, असंवैधानिक, जल्दबाजी में और पक्षपातपूर्ण थी। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम लागू किए गए। कई सही वोटों के नाम काटे गये। अदालत के हस्तक्षेप के बाद कुछ नाम जोड़े गए, लेकिन अभी भी बहुत से नाम बाहर रहे। टीएमसी ने मतगणना के दौरान भी धांधली के आरोप लगाए थे। ममता का आरोप था कि गिनती केंद्रों पर टीएमसी के काउंटिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। ईवीएम में हेराफेरी का आरोप भी लगाया गया।

बंगाल की जिस चुनाव प्रक्रिया पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही हैं उसमें इस्तेमाल की गई करीब 4000 ईवीएम जल कर नष्ट हो गई। कोलकाता की एक सरकारी इमारत में आग लगी जिसमें ये ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखी हुई थीं। ये EVM इस साल हुए विधानसभा चुनावों में 10 सीटों पर इस्तेमाल की गई थीं। राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा है कि यह आग सामान्य नहीं लग रही है। उन्होंने साजिश की आशंका जताई है। मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि आग तीसरी मंजिला पर शुरू हुई, लेकिन चौथी, पांचवीं और छठी मंजिला को छोड़कर सीधे सातवीं और आठवीं मंजिल तक पहुंच गई। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि आग बीच की मंजिलों को छोड़कर ऊपर कैसे पहुंची? रिपोर्ट के अनुसार कौशिक चौधरी ने कहा, यह सामान्य आग नहीं दिख रही है। हम साजिश की आशंका की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने सैपल लेने के लिए मीके पर पहुंची। रिपोर्ट है कि पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। EVM जलने से चुनावी दस्तावेजों और अन्य सरकारी सामान को भी नुकसान पहुंचा है। आग दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक

गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, 4 की मौत

उन्नाव, 12 जून (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। उन्नाव से दर्दनाक हादसा सामने आया है। गंगा एक्सप्रेसवे-वे पर प्रयागराज से आ रही टाटा पंच कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से लड़ गई। हादसे में कार सवार 2 की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रैन की मदद से कार को सड़क से किनारे हटवाया। जानकारी के मुताबिक, घटना आसीवन थाना क्षेत्र में हुई। बताया जा रहा है हादसे के समय कार की स्पीड करीब 100 किमी प्रति घंटे की रही होगी। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर कार पर कंट्रोल खो बैठा और सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया।

कलंक-भय का मिटा निशान आजमगढ़ अब यूपी की शान

अभि-मुनियों की पावन भूमि आजमगढ़ में ₹955 करोड़+ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास

द्वारा **योगी आदित्यनाथ** मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

गौरमाधवी उपस्थिति

अनिल राजभर मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय, उत्तर प्रदेश	दारा सिंह चौहान मंत्री, कारागार, उत्तर प्रदेश
विजय बहादुर पाठक सदस्य, विधान परिषद	राम सुत राजभर सदस्य, विधान परिषद
विक्रान्त सिंह 'रिशु' सदस्य, विधान परिषद	एवं अन्य गणमान्य महानुभाव

प्रमुख आकर्षण : वृक्षारोपण | विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी

आजमगढ़ सड़क : ₹29 करोड़ की लागत से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मंडलीय कार्यालय भवन | ₹16 करोड़ से सारथी हॉल सहित संगीत/सहायक संगीतगीत परिवहन कार्यालय एवं ऑटोमैटिक इंडस्ट्री ट्रेनिंग ट्रक | ₹3 करोड़ से राजकीय होमोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 3 अलासट्रूम

मुबारकपुर : ₹2 करोड़ से महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ परिसर की चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाये जाने संबंधी कार्य | ₹15 करोड़ से क्षेत्र पंचायत सविवाय के सिकंदरपुर घाट (तमसा नदी) पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक कार्य | ₹93 लाख से मुबारकपुर सोफी कुटी स्थित हुनगम मंदिर का पर्यटन विकास

आजमगढ़ सड़क : ₹717 करोड़ से तमसा गाँव एनक्लेव का निर्माण कार्य | ₹12 करोड़ से पुलिस लाइन परिसर में 200 कमरों हेतु जी-11 बैच/हॉस्टल का निर्माण कार्य | ₹1 करोड़ से थाना तहबरपुर एवं थाना रौनपार में बाउंड्रीवॉल एवं पेन गेट का निर्माण कार्य

शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं

मुबारकपुर : ₹30 करोड़ से क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना का कार्य | ₹23 करोड़ से विकास खंड-जहानागंज में मुख्यमंत्री मंडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कार्य | ₹21 करोड़ से नर्सिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर, चक्रपामपुर का निर्माण कार्य

दिनांक : 13 जून, 2026 | समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे
स्थान : महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रगति पत्र 12 वर्ष

विकास की गति अपार डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
साइबर प्रसारण DD NEWS & Youtube.com/DDNEWS

खुदरा महंगाई के बोझ से दबा आम आदमी

नई दिल्ली, 12 जून (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर मई महीने में 3.93% पर पहुंच गई है। महंगाई में तेजी के बावजूद यह लगातार 16वें महीने में आरबीआई की सीमा 4: से नीचे बनी रही। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। देश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाया है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 फीसदी हो गई है। यह पिछले महीने अप्रैल की 3.48 फीसदी से अधिक है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि इसका कारण बनी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खाद्य महंगाई मई में 4.78 फीसदी रही। अप्रैल में यह 4.2 फीसदी थी। यह वृद्धि सीधे तौर पर रसोई के बजट को प्रभावित कर रही है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को परिवारों पर इसका अधिक असर दिख रहा है। महंगाई का यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के

लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई को चार फीसदी पर रखने का लक्ष्य दिया है। इसमें दो फीसदी ऊपर या नीचे का मार्जिन भी शामिल है। यह लक्ष्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ती महंगाई से आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कीमती धातु के आभूषण, टमाटर और अदरक उन पांच वस्तुओं में शामिल हैं। किशमिश और मुनक्का भी अधिक महंगाई वाली वस्तुओं की सूची में हैं। इन वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। यह सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के खर्च को बढ़ा रहा है। विशेष रूप से टमाटर और अदरक जैसी रोजमर्रा की सब्जियों की कीमतों में वृद्धि चिंताजनक है। इससे दैनिक जीवन की लागत बढ़ गई है। दूसरी ओर, कुछ वस्तुओं की कीमतों में कम वृद्धि देखी गई। आलू, मटर, मोटर कार और जीप की महंगाई कम रही। जीरा और मोटरसाइकिल तथा स्कूटर भी कम महंगाई वाली शीर्ष पांच वस्तुओं में शामिल थे। यह आंकड़ा अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से दर्ज किया गया है। यह दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं।

तमाम दावों के बावजूद हिंसा और यौन अपराधों का शिकार हो रही हैं महिलाएं

यू तो भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के तमाम दावे गाहे-बगाहे किए ही जाते हैं। आधी दुनिया को पूरा हक देने की बात होती है। किंतु-परंतु के बीच उन्हें जनप्रतिनिधि संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने पर प्रतिबद्धता जतायी जाती है। लेकिन इन दावों के बीच सामने आया एक कड़वा सच हमें वास्तविक स्थिति से रूबरू करा देता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती रही है। यह विडंबना ही है कि शहरों की तुलना में ज्यादा शांत व सुरक्षित माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ता है। वीरवार को सुप्रीम

कोर्ट ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें नेशन बिलडर तक कह दिया। यहां तक कि घर और परिवार की देखभाल में गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कल्पित आर्थिक मूल्य का निर्धारण करते हुए उसे नजरअंदाज न करने की सलाह दी। यह विडंबना ही है कि जिन महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट नेशन बिलडर बता रहा है, उन्हें हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आखिर महिला सशक्तीकरण के सारे विशेष प्रयास सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि महिलाओं की रक्षा-सुरक्षा हेतु तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। इसमें दो राय नहीं कि समय-समय पर महिला उत्थान के लिये तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान चलाये जाते रहे हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जीवन के हर क्षेत्र में वे अपना आकाश तलाश रही हैं। विधायिका में तैतीस प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल सहमत नजर आते हैं। सवाल यही है कि जीवन व्यवहार में स्थिति क्यों नहीं बदलती। देश के नीति-नियंताओं को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौथी व शहरी क्षेत्र में हर छठी स्त्री को हिंसा व यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि घर से लेकर बाहर तक वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं? क्या कहीं इसमें पितृसत्ता प्रधान समाज की मानसिकता कारण है?

कामकाजी के लिए परफेक्ट हैं ये हैंड बैग, बढ़ायेंगे आपकी शोभा



अगर आप भी वकिंग बुमन हैं और रोजाना ऑफिस जाती हैं। तो आप भी अपने लुक को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं। बता दें कि आप अपने ऑफिस लुक में चार चांद लगाने के लिए कुछ लेटेस्ट और नए डिजाइन वाले हैंडबैग को शामिल कर सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे हैंड बैग डिजाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें आप अपनी जरूरत का सभी सामान आराम से रख सकती हैं। वहीं इन हैंड बैग को ऑफिस लुक में शामिल कर स्टाइलिश लुक पा सकती हैं।

ग्रीन एंड व्हाइट कलर हैंड बैग
 आप ऑफिस लुक में इस तरह के खूबसूरत हैंड बैग को शामिल कर सकती हैं। आप किसी भी तरह के आउटफिट के साथ इस हैंड बैग को शामिल कर अपने लुक को कंपटी कर सकती हैं। अधिकतर महिलाओं को ऐसे हैंड बैग के डिजाइंस पहली पसंद बने हुए हैं। यह हैंड बैग आपके लिए परफेक्ट हैं।

ओवरसाइज्ड डबल पॉकेट टोट बैग
 अगर आपको भी खूबसूरत हैंड बैग पसंद हैं, आपको हमेशा नए और लेटेस्ट डिजाइन वाले हैंड बैग की तलाश में रहती हैं। तो आपको परेशान होने की बजाय इस तरह के ओवरसाइज्ड डबल पॉकेट टोट बैग को शामिल कर सकती हैं। यह आपके ऑफिस लुक को खास बना सकता है।

डेनिस ओवरसाइज्ड डिटेचेबल रिंग्स हैंड बैग
 अगर आप ऑफिस में एक जैसा हैंड बैग लो जाकर परेशान हो गई हैं और कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोच रही हैं, तो आपको इस तरह का ओवरसाइज्ड डिटेचेबल रिंग्स हैंड बैग शामिल करना चाहिए।

डिटेचेबल स्ट्रैप ब्राउन ऑफिस बैग
 अगर आप रॉयल लुक पाना चाहती हैं, तो ऑफिस में डिटेचेबल स्ट्रैप ब्राउन बैग शामिल कर अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं। आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर इस तरह के बैग आसानी से मिल जाएंगे। या फिर मार्केट से भी इस तरह के बैग खरीद सकती हैं।

डबल हैंडल शोल्डर स्ट्रैप लेडर हैंडक्राफ्टेड बैग
 डबल हैंडल शोल्डर स्ट्रैप लेडर हैंडक्राफ्टेड बैग भी आपको बेस्ट लुक दे सकता है। यह न सिर्फ आपके ऑफिस लुक को स्टाइलिश बनाएगा, बल्कि इसमें सभी जरूरत का सामान भी आसानी से रख पाएंगी। क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। आप इसमें लैपटॉप भी आसानी से रख सकती हैं।

बरागंडी कलर का स्टाइलिश हैंड बैग
 इस तरह का खूबसूरत बरागंडी कलर का स्टाइलिश हैंड बैग लेकर भी ऑफिस जा सकती हैं। इन दिनों यह हैंड बैग डिजाइंस ज्यादातर महिलाओं की पसंद बने हैं। जो आपके लिए भी परफेक्ट हो सकते हैं। इस तरह के बैग आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से मिल जाएंगे।

शी के उत्तर कोरिया दौरे से सतर्क अमेरिका

● पुष्परजन जैन

जिस परमाणु ताकत की आशंका को लेकर ट्रम्प ने ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उत्तर कोरिया के मामले में चुपची है। ट्रम्प की हिम्मत नहीं, कि उत्तर कोरियाई लीडरशिप के विरुद्ध एक शब्द बोल दें। ट्रम्प उत्तर कोरिया के मुंहफट नेता से दूरी बनाये रखना चाहते हैं। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने तेजी से अपना परमाणु शस्त्रागार बढ़ाया है, और एक परमाणु-सम्पन्न राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया है। उत्तर कोरिया ने हमेशा चीन और रूस के बीच बराबर की लड़ाई बनाए रखने वाली कूटनीति अपनाई है, या दोनों के बीच संतुलन बनाकर चला है, इसलिए वह चीन के साथ ऐसे किसी भी मिलिट्री सहयोग को लेकर सतर्क है, जो हार्ड लाइनर को पार करता हो।

26 अप्रैल, 2026 को, उत्तर कोरिया ने विदेशी सैन्य अभियानों का स्मारक संग्रहालय खोला। यह संग्रहालय उन सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक ऐसी छद्मताम्यताी सैन्य नीति का पुष्टि की है जिसके तहत रूस-यूक्रेन युद्ध में शामिल सैनिकों को पकड़े जाने से बचने के लिए युद्ध के मैदान में आत्महत्या करनी होगी। इसी साल फरवरी में, दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने खबर दी थी, कि रूस-यूक्रेन युद्ध में 6,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए, या घायल हुए हैं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने बताया, कि फरवरी, 2026 तक, रूस के अग्रिम मोर्चे वाले कुस्कू ओब्लास्ट में लगभग 11,000 उत्तर

कोरियाई सैनिक तैनात थे। इनमें से 10,000 लड़ाकू सैनिक थे, और 1,000 इंजीनियरिंग सेवा के सैनिक थे।

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की ताकत रूस और चीन की वजह से है। इसी वजह से गाहे-बगाहे ट्रम्प को ललकारते हैं, चुनौतियाँ किम जोंग उन, पुतिन और शी दोनों से समान संतुलन बनाये रखना चाहते हैं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने कहा, रूस में

सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा, कि उसके झोला का इस्तेमाल ईरान कर रहा है? प्योंगयांग द्वारा अपने झोला का ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की संभावना बहुत कम है। उत्तर कोरिया की नीति हमेशा हथियारों के गुप्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने की रही है। इसके बजाय, वे इस तरह के मामलों में रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखना पसंद करते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि उत्तर कोरिया और ईरान के बीच झोला और मिसाइल तकनीक का गहरा आदान-प्रदान रहा है। कई उत्तर कोरियाई झोले, ईरान के शाहेद सीरीज के ड्रोन्स से काफी मिलते-जुलते हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हूआ के अनुसार, सोमवार को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों को कूटनीति, कानून प्रवर्तन और सैन्य मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा

रणनीतिक बातचीत को मजबूत करने के वादों के बावजूद, बैठक के बाद जारी बयानों में कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु-निस्त्रीकरण का कोई जिक्र नहीं था, जो 2019 में शी की पिछली यात्रा से बिल्कुल अलग बात है। अपनी पिछली मुलाकातों से अलग, इस बार शी और किम के साथ उनके रक्षा मंत्री, डोंग जून और नो क्वांग-चोल भी थे। 1992 के बाद यह पहली बार है, जब चीन के रक्षा मंत्री, चीनी राष्ट्रपति के साथ उत्तर कोरिया गए।

यह भी पहली बार है, जब चीन के किसी सीनियर रक्षा अधिकारी ने उत्तर कोरिया का दौरा किया है; इससे पहले 2019 में चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के तत्कालीन डायरेक्टर मियाओ हुआ ने वहां का दौरा किया था। हालांकि, खबरों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में छह साल में पहली बार चीन का एक मिलिट्री डेलिगेशन उत्तर कोरिया गया था, लेकिन उस डेलिगेशन के स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस हफ्ते मिलिट्री मामलों को जो अहमियत दी गई, वह आर्थिक और कूटनीतिक मामलों जैसी पारंपरिक प्राथमिकताओं के अलावा थी। शी के आने से एक दिन पहले- किम की बहन किम यो-जोंग ने कहा कि परमाणु शक्ति के तौर पर उत्तर कोरिया का दर्जा एक हथियार और कभी न बदलने वाली हकीकत है, और अमेरिका जैसी ह्युमन ताकतों को परमाणु हथियार खत्म करने की अपनी गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए। शी के आने से पहले उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया रीडिंग सिनयून में छपे एक लेख में, उन्होंने वर्चस्ववाद और ताकत की राजनीति, और ऐसी सभी महत्वकांक्षाओं और साजिशों का विरोध करने पर जोर दिया, जो सैन्यवाद को फिर से जिंदा करना चाहती हैं, और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरों में डालती हैं। हैरत की बात है, कि उस आलेख में परमाणु हथियार खत्म करने (डी-न्यूक्लियराइजेशन) का कोई जिक्र नहीं था। एक सच तो है, कि अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया और जापान के साथ गठबंधन मजबूत करने के जवाब में चीन, परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया को अपने प्रभाव में ला रहा है!

लेखक जियो-पॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।



चीन और उत्तर कोरिया के बीच मिलिट्री सहयोग बढ़ने की संभावना ऐसे समय में बनी है, जब प्योंगयांग अपने न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियारों के प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते शी के दौरे की घोषणा से एक दिन पहले, उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बताया कि किम ने हाल ही में न्यूक्लियर मटीरियल बनाने वाले एक नए प्लांट का दौरा किया, और न्यूक्लियर ताकत को तेजी से मजबूत करने का वादा देश से किया था। जिस परमाणु ताकत की आशंका को लेकर ट्रम्प ने ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उत्तर

कोरिया के मामले में चुपची है। ट्रम्प की हिम्मत नहीं, कि उत्तर कोरियाई लीडरशिप के विरुद्ध एक शब्द बोल दें। ट्रम्प उत्तर कोरिया के मुंहफट नेता से दूरी बनाये रखना चाहते हैं। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने तेजी से अपना परमाणु शस्त्रागार बढ़ाया है, और एक परमाणु-सम्पन्न राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया है। उत्तर कोरिया ने हमेशा चीन और रूस के बीच बराबर की लड़ाई बनाए रखने वाली कूटनीति अपनाई है, या दोनों के बीच संतुलन बनाकर चला है, इसलिए वह चीन के साथ ऐसे किसी भी मिलिट्री सहयोग को लेकर सतर्क है, जो हार्ड लाइनर को पार करता हो।

6,000 सैनिकों के हताहत होने के बावजूद, उत्तर कोरियाई सेना ने युद्ध के मैदान में आधुनिक युद्ध-कौशल और डेटा इकटिा कर रहे हैं। साथ-साथ रूस की तकनीकी मदद से अपने हथियार प्रणालियों को अपग्रेड करने में सफलता पाई है। एजेंसी ने यह भी बताया, कि प्योंगयांग ने एक नया यूएवी ड्रोन विभाग बनाया है, और वह ऐसे सिस्टम को स्थापित करने पर काम कर रहा है, जो ड्रोन विकसित करने और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम हो।

लेकिन, क्या उत्तर कोरिया यह रणनीतिक बातचीत को मजबूत करने के वादों के बावजूद, बैठक के बाद जारी बयानों में कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु-निस्त्रीकरण का कोई जिक्र नहीं था, जो 2019 में शी की पिछली यात्रा से बिल्कुल अलग बात है। अपनी पिछली मुलाकातों से अलग, इस बार शी और किम के साथ उनके रक्षा मंत्री, डोंग जून और नो क्वांग-चोल भी थे। 1992 के बाद यह पहली बार है, जब चीन के रक्षा मंत्री, चीनी राष्ट्रपति के साथ उत्तर कोरिया गए। यह भी पहली बार है, जब चीन के किसी सीनियर रक्षा अधिकारी ने उत्तर कोरिया का

सिने जगत

काम दिलाने की आड़ में ढगे गए 20 लाख रुपए-नोरा फतेही



मुंबई की चमक-दमक के पीछे ठगी, ताने और संघर्ष की लंबी कहानी भी छुपी है। नोरा फतेही की जिंदगी भी ऐसी ही रही, जहाँ काम दिलाने का वादा कर 20 लाख रुपए ठग लिए गए और कई बार उन्हें बिना फीस के गाने करने पड़े। हमें मजाक उड़ाना गया, दिलबर जैसे कई गाने फ्री में करने पड़े- यह दौर उनकी पहचान बनने से पहले के संघर्ष को दिखाता है।

कनाडा से मुंबई आई नोरा ने वेटर से लेकर ऑडिशन तक हर रास्ता अपनाया, लेकिन हार नहीं मानी। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी स्टारडम की सबसे बड़ी ताकत बना। नोरा का जन्म एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ। घर में डांस को लेकर कड़ा विरोध था, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही डांस का जुनून था। उन्होंने कभी प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग नहीं ली। वे अलग-अलग डांस स्टाइल्स वीडियो देखकर और लगातार प्रैक्टिस से सीखती रहीं।

नोरा बचपन में घर के अंदर बंद कमरे में छिपकर डांस करती थीं। उन्हें डर रहता था कि परिवार को पता चल गया तो डांट पड़ेगी। एक बार उनकी मां ने उन्हें डांस करत देख लिया, जिसके बाद उन्हें डांट और सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यहां तक की मां ने पिटाई भी की विरोध के बावजूद नोरा ने डांस करना नहीं छोड़ा और अपने सपनों

सिखी और खुद को परफॉर्मर के तौर पर तैयार किया।

नोरा कहती हैं- मैंने बॉलीवुड में कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा था। इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने हॉटेवदास और हलकुछ कुछ होता है जैसी फिल्में देखी थीं। मुझे लगता था कि सिर्फ इंडियन लड़कियां ही बॉलीवुड में पकड़े बन सकती हैं। बॉलीवुड में काम करने की प्रेरणा मुझे कैटीरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस से मिली। फिर मैंने बहुत ऑडिशन देने शुरू किए।

स्ट्रगल के दिनों में आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें गुजारे के लिए छोटे-मोटे काम करने पड़े। नोरा ने कॉफी शॉप में वेटर का काम किया और लॉटरी टिकट भी बेचे। मॉडलिंग और छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, लेकिन कई बार काम के बाद भी भुगतान नहीं मिलता था।

नोरा के लिए सबसे मुश्किल समय वह था जब पैसे की कमी के कारण उन्हें खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि कई बार दिनभर सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मुंबई छोड़ने का विचार नहीं किया और अपने सपनों के लिए डटती रहीं। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नोरा फतेही कहती हैं कि उस समय जिस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, वह उन्हें हफ्ते के सिर्फ 3 हजार रुपए देती थी। इतने कम पैसे में रोज का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। बॉलीवुड में पहचान बनाने से पहले भरे साथ ठगी हुई। मैंने बताया था कि जब मैं कनाडा से भारत आई थी, तब मेरी पहली एजेंसी ने मुझे काम दिलाने का वादा किया। उनके कहने पर मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बाद में उनका व्यवहार बदल गया। जब मैंने एजेंसी छोड़ी और पैसे वापस मांगने की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की निर्णायक अडथाल है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेम्फुरियो सहित केंद्र, दिनभर सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मुंबई छोड़ने का विचार नहीं किया और अपने सपनों के लिए डटती रहीं। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नोरा फतेही कहती हैं कि उस समय जिस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, वह उन्हें हफ्ते के सिर्फ 3 हजार रुपए देती थी। इतने कम पैसे में रोज का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। बॉलीवुड में पहचान बनाने से पहले भरे साथ ठगी हुई। मैंने बताया था कि जब मैं कनाडा से भारत आई थी, तब मेरी पहली एजेंसी ने मुझे काम दिलाने का वादा किया। उनके कहने पर मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बाद में उनका व्यवहार बदल गया। जब मैंने एजेंसी छोड़ी और पैसे वापस मांगने की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की निर्णायक अडथाल है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेम्फुरियो सहित केंद्र, दिनभर सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मुंबई छोड़ने का विचार नहीं किया और अपने सपनों के लिए डटती रहीं। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नोरा फतेही कहती हैं कि उस समय जिस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, वह उन्हें हफ्ते के सिर्फ 3 हजार रुपए देती थी। इतने कम पैसे में रोज का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। बॉलीवुड में पहचान बनाने से पहले भरे साथ ठगी हुई। मैंने बताया था कि जब मैं कनाडा से भारत आई थी, तब मेरी पहली एजेंसी ने मुझे काम दिलाने का वादा किया। उनके कहने पर मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बाद में उनका व्यवहार बदल गया। जब मैंने एजेंसी छोड़ी और पैसे वापस मांगने की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की निर्णायक अडथाल है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेम्फुरियो सहित केंद्र, दिनभर सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मुंबई छोड़ने का विचार नहीं किया और अपने सपनों के लिए डटती रहीं। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नोरा फतेही कहती हैं कि उस समय जिस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, वह उन्हें हफ्ते के सिर्फ 3 हजार रुपए देती थी। इतने कम पैसे में रोज का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। बॉलीवुड में पहचान बनाने से पहले भरे साथ ठगी हुई। मैंने बताया था कि जब मैं कनाडा से भारत आई थी, तब मेरी पहली एजेंसी ने मुझे काम दिलाने का वादा किया। उनके कहने पर मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बाद में उनका व्यवहार बदल गया। जब मैंने एजेंसी छोड़ी और पैसे वापस मांगने की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की निर्णायक अडथाल है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेम्फुरियो सहित केंद्र, दिनभर सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मुंबई छोड़ने का विचार नहीं किया और अपने सपनों के लिए डटती रहीं। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नोरा फतेही कहती हैं कि उस समय जिस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, वह उन्हें हफ्ते के सिर्फ 3 हजार रुपए देती थी। इतने कम पैसे में रोज का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। बॉलीवुड में पहचान बनाने से पहले भरे साथ ठगी हुई। मैंने बताया था कि जब मैं कनाडा से भारत आई थी, तब मेरी पहली एजेंसी ने मुझे काम दिलाने का वादा किया। उनके कहने पर मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बाद में उनका व्यवहार बदल गया। जब मैंने एजेंसी छोड़ी और पैसे वापस मांगने की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की निर्णायक अडथाल है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेम्फुरियो सहित केंद्र, दिनभर सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मुंबई छोड़ने का विचार नहीं किया और अपने सपनों के लिए डटती रहीं। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नोरा फतेही कहती हैं कि उस समय जिस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, वह उन्हें हफ्ते के सिर्फ 3 हजार रुपए देती थी। इतने कम पैसे में रोज का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। बॉलीवुड में पहचान बनाने से पहले भरे साथ ठगी हुई। मैंने बताया था कि जब मैं कनाडा से भारत आई थी, तब मेरी पहली एजेंसी ने मुझे काम दिलाने का वादा किया। उनके कहने पर मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बाद में उनका व्यवहार बदल गया। जब मैंने एजेंसी छोड़ी और पैसे वापस मांगने की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे।



अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता से संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करें - जिलाधिकारी

आईजीआरए पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण न किए जाने के कारण 57 अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। जिलाधिकारी आनंद चहलान की अध्यक्षता में कर एवं करेतर राजस्व तथा आईजीआरए प्रकरणों की जनपदीय मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के कार्यालय में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की माह मई 2026 को राजस्व प्राप्तियों एवं शिकायत निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान व्यापार कर की प्रगति 51.30 प्रतिशत, स्टॉप एवं रजिस्ट्रेशन 80.15 प्रतिशत, परिवहन कर 95.88 प्रतिशत, आबकारी 87.39 प्रतिशत, वन विभाग 76.59 प्रतिशत, खनन 78.47 प्रतिशत, भू-राजस्व 17.63 प्रतिशत, विद्युत देय 53.43 प्रतिशत, बैंक देय 113.52 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 8.73 प्रतिशत, सड़क एवं पुल 19.44 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों

की प्रगति 91.38 प्रतिशत पाई गई। इस प्रकार माह मई की कुल प्रगति 72.18 प्रतिशत रही जिलाधिकारी ने व्यापार कर एवं अन्य कम प्रगति वाले विभागों को अपने राजस्व संग्रह में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को जनपद के सभी ईट-भट्टों का सघन निरीक्षण करने तथा अवैध खनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्टॉप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति न होने के कारणों से अवगत कराने हेतु सहायक महानिरीक्षक निबंधन को निर्देशित किया।

बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए



कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा स्वयं शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित कर उनकी संतुष्टि प्राप्त की जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क कर समस्याओं का समाधान करें तथा संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

आईजीआरए एवं मुख्यमंत्री

हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डी श्रेणी में आने वाले विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि आगामी समीक्षा तक ए श्रेणी प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण कर जनपद की रैंकिंग में सुधार लाना सभी अधिकारियों को प्राथमिक जिम्मेदारी है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी ए डी श्रेणी में आने वाले विभागों को लापरवाही किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरता पाया गया तो उसके विरुद्ध शासन स्तर पर पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के दौरान आईजीआरए पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण न किए जाने के कारण 57

अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरए एवं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कई विभागों में असंतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत अधिक है, जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 जून 2026 तक संतुष्टि का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक करते हुए असंतुष्ट आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा अपना स्पष्टीकरण जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

मुख्य जिलाधिकारी प्रवेद कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश, समस्त उप जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रोजगार मेले का आयोजन 16 जून को

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 16 जून 26, समय प्रातः 10 बजे:स्थान, सेवायोजन कार्यालय के प्रांगण में रोजगार मेला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें निजी क्षेत्र की कम्पनी- रोशनी एंटरप्राइजेज (सीआर०३ प्रा०लि० अहमदाबाद), उम्र 18 से 60 वर्ष कार्यस्थल जामनगर, देहेज भुज अहमदाबाद, शैक्षिक 8वें, 10वें पाँस (अशिक्षित व्यक्ति भी इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं), वेतन- 17000-37000, पद-कारपेन्टर, बाबेन्डर, मैशन (राजमिस्त्री), हेल्पर, फिटर, रिगर, गैस कटर, वेल्डर, सुपरवाइजर, फोरमैन रिगर, इलेक्ट्रिशियन, इत्यादी पदों पर बेरोजगार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। मेले में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है, पंजीकृत अभ्यर्थियों का कैम्पस चयन रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से होगा।

नगरपालिका ने हनुमान नगर कालोनी से हटाया अतिक्रमण

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। अधिशासी अधिकारी डा. मणि भूपण तिवारी के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में राजस्व निरीक्षक अमृता राय के नेतृत्व में हनुमान नगर कालोनी में नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाया गया।

यातायात के नियमों का पालन न करने पर 509 वाहनों को विभिन्न धाराओं में चालान एवं वाहन को सीज

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन में शुक्रवार को समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत सतिध वक्तियों/वाहनों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लाभग सतिध वाहनों/वक्तियों को चेक किया। जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 509 वाहनों को विभिन्न धाराओं में चालान एवं 01 वाहन को सीज किया। साथ ही साथ अन्य लोगों को हिरासत दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील किया कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेमलेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नहीं करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

ई-समन सामल, थानाध्यक्षों को जारी किया निर्देश

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक मऊ ने जनपद के विभिन्न थानों में लॉन्ग पड़े ई-समन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थानाध्यक्षों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि 12 जून 2026 को ई-समन पोर्टल के दैनिक सांख्यिकीय चार्ट के अवलोकन में पाया गया कि कड़े थानों पर ई-समन के मामलों की संख्या काफी अधिक लॉन्ग है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इनके निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पत्र के अनुसार सराबलखंसी एवं मधुवन थाने में 34-34, घोसी कोतवाली में 51 तथा मुहम्मदाबाद थाने में 25 ई-समन प्रकरण अनुपालन हेतु लॉन्ग पा गए हैं। एसपी ने संबंधित प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं विशेष रुचि लेकर लॉन्ग मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा समयबद्ध कार्रवाई न करने वाले थाना प्रभारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित क्षेत्राधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने निरुक्त पर्यवेक्षण में लॉन्ग ई-समन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

दुर्घम व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर एवं स्वाट/एसओजी/सिविलों की संयुक्त टीम ने पूर्वांचल एक्सप्रववे जम्हू अंडरपास के पास मु0अ0स0 072/2026, धारा 65(1), 123, भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 पाँसो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत निवासीगण कमालपुर बमनपुरा थाना मुहम्मदाबाद गौहना को गिरफ्तार किया। तपन्ती और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) और 61(2) (आपराधिक साजिश) की बढ़ोतरी की गई है अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय किया। प्रकाश में आये घटना में सलिल एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

संतों ने मूर्ति बरामदगी के लिए दिया ज्ञापन

बलिया, 12 जून (देवव्रत संवाद)। बलिया के सृष्णाली स्थित राम जानकी मंदिर से चोरी हुई मूर्तियों की बरामदगी को लेकर संतों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि मूर्तियाँ बरामद नहीं हुईं, तो संत समाज आमरण अनशन करेगा। यह पत्रक कमलानयन दास कृष्णा जी की ओर से दिया गया है। संतों ने बताया कि मंदिर से लड्डुगोपाल, राधाकृष्ण की युगल मूर्ति और हनुमान जी की मूर्तियाँ चोरी हुई हैं। इस संबंध में पांच सहोंने पहले थाना नगरा में प्रार्थनाओं दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में आठ चोरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, गिरफ्तारी के बावजूद आज तक मूर्तियाँ बरामद नहीं हो पाई हैं। संतों का आरोप है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर विवेचना समाप्त कर दी गई है और चांरजीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है। मूर्तियाँ बरामद न होने से पूजा-पाठ में बाधा आ रही है। संतों ने मांग की है कि थानाध्यक्ष नगरा और सीओ रसड़ा को तत्काल मूर्तियाँ बरामद करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे पूरे संत समाज के साथ डीएन कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति, सास और ससुर को 7 वर्ष की सजा

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक दीप नारायण तिवारी ने प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के मामले में नामजद 4 आरोपियों में सुनवाई के बाद पति, सास और ससुर को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद तीनों को सात-सात वर्ष की सजा के साथ ही कुल 6-6 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 15 हजार रुपए वादिनी मुकदमा को देने का आदेश दिया। एक आरोपी को सहेह का लाभ देने हेतु दोष मुक्त कर दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र के कलाफनपुर गांव का है।

उसकी पुत्री आरती को आरोपीगण प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेज के लिए 13 दिसंबर 22 को आरती की हत्या कर दिए। मामलों में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पेश की गई एचडीसी फौजदारी राजेश कुमार पांडेय और अनिल कुमार पांडेय ने कुल 7 गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पर एक गवाह को पेशकर तर्क दिया गया कि उन्हें झूठा फसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा प्रभावों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण पति नितेश चौहान, ससुर तुफानी चौहान और सास सावित्री देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद तीनों को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सात-सात वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। वहीं प्रताड़ना के मामले में 3-3 वर्ष की सजा के साथ ही 1-1 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अर्थदंड जमा हो जाने पर 15 हजार रुपए वादिनी मुकदमा उर्मिला देवी को देने का आदेश दिया।

सरकार के विरुद्ध उनकी गलत नीतियों भ्रष्टाचार की गंगोत्री पर प्रहार

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। समाजवादी पार्टी द्वारा शुक्रवार को सरकार के विरुद्ध उनकी गलत नीतियों भ्रष्टाचार की गंगोत्री पर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व पार्टी नेता विधायक के साथ जिलाधिकारी से मिलकर 10 अप्रैल 2026 को जारी मतदाता सूची में भारी विसंगतियों को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बड़े संख्या में एक ही नाम माता-पिता एक उम्र सहित अलग-अलग इपिक नंबर अनेकों बार सैकडों बूथ का पाया। जिससे लेकर जिलाधिकारी से वार्ता एवं डबल ट्रिपल बोगस नाम डिलीट की मांग की गई वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री पर अराजक तत्वों द्वारा गलत पोस्ट किए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक से तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। उसके उपरांत जिला पार्टी कार्यालय पर एक प्रेत वार्ता जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव ने उत्तर प्रदेश में नौकरी हेतु 22 परीक्षाओं में मिलाकर पीडीए समाज के लोगों का 11514 नौकरी के पद लूट लिया। जिसका विधिवत विवरण जिलाध्यक्ष ने जारी कर दिया जिसमें मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती में 7933 वन जीव रक्षक भर्ती में 88 एग्रीकल्चर जूनियरिस्टी में पांच एडेड जूनियर हाई स्कूल हेडमास्टर 547 ग्राम पंचायत अधिकारी 232 नेट परीक्षण अधिकारी 47 यूपी एएसएस कीनक्ष सहायक 300 प्रवर्तन मास्टेबल भर्ती 34 लखीमपुर को ऑपरेटिव बैंक में भर्ती 8 यूपीएससी आशुलिपि 37 यूपीएससी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 434



लेखपाल भर्ती 960 पशु चिकित्सक भर्ती 81 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती 55 चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद 54 का अधिकारी हो उपाय दो अमीन नीलामी करता 19 यूपीएससी लिपिक टैकर जो यूपीएससी सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 58 यूपीएससी अधिशासी अधिकारी भर्ती 13 यूपीएससी सहायक चक्रबंदी अधिकारी भर्ती 10 यूपीएससी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 588 पदा के पदों पर डाका डाला। जिससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान की सरकार ने किया है और पीडीए के जो लोग कम पड़े लिखे हैं या उनका राजनीतिक ज्ञान नहीं है वह सरकार द्वारा हिंदू मुस्लिम मजिल मस्जिद में उलझ कर सरकार भाजपा का बनाकर अपना नुकसान कर

दिए हैं। आज उनके संतान इस बात पर खीझ रही है कि यह सरकार अपने लोगों ने नहीं बनाया होता तो हम लोगों का हक पर डाका नहीं डाला गया होता। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र कुमार, राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान, प्रदेश सचिव जिला महासचिव कुकूस अंसारी, महेंद्र चौहान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री हरिहरद्वारा एवं पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र यादव साधु, शिव प्रताप यादव मुन्ना, देवनाथ यादव, जिला कोषाध्यक्ष, रामधनी चौहान, राजेश यादव, अप्पू मौय्य, पंकज उपाध्याय जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष लालचंद्र यादव, सितारा यादव, नीलम भारती, रनेश भारती अफजल अलंकार, अमरेंद्र बहादुर, आदि उपस्थित रहे।

चित्रकला कार्यशाला का हुआ समापन, बच्चों की प्रतिभा को मिली सराहना



कोषागंज (मऊ)। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, संस्कार भारती मऊ कोषागंज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला का समापन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार विश्वकर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यापूर्ण एवं पुष्पार्चन कर किया। इसके बाद उन्होंने कार्यशाला में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ. सुनील कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा के साथ जीवन पोषण का सशक्त साधन भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. सुनील सिंह कुशवाहा ने कहा कि कला संस्कृति की सहभागिनी है और समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संतोष पांडेय रहे। कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी 105 बच्चों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य डॉ. प्रफुल्ल चंद, पूर्वी संसार के संपादक ओमप्रकाश गुप्त, संस्कार भारती के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद राय, जिला महामंत्री प्रेम नारायण कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा, उपकोषाध्यक्ष राकेश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष चंद्रमणि पांडेय सहित संजय गुप्ता, अनिल मोहं, डॉ. अरुण मिश्रा, योगेंद्र मोहं, दीपक वर्मा, सुदामा वर्मा, डॉ. अजय शर्मा, श्यामजी शाहनी, श्रवण विश्वकर्मा, सलोनी गुप्ता आदि मौजूद रहे कार्यक्रम का संचालन विनोद बरनवाल ने किया।

केन्द्र सरकार के 12 वर्ष व राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर नगरपालिका ने चलाया पर्यावरण संरक्षण व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। केंद्र सरकार के 12 वर्ष व राज्य सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून 2026 तक संचालित हो रहे विशेष जनकल्याण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा क्षेत्र के सभी वार्डों व मलिन बस्तियों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के लिये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत जन संपर्क एवं रैलियाँ आयोजित की जा रही हैं। अधिशासी अधिकारी डा. मणि भूपण तिवारी ने बताया कि नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से आईपीसी (आईईसी) टीम द्वारा वार्ड नं0 5, 11, 12, 23, एवं 35 आदि में घर-घर जाकर आम लोगों को जागरूक किया। टीम द्वारा नागरिकों को कूड़ा पृथक्करण, चार डस्टबिन प्रणाली अपनाने, होम कम्पोस्टिंग सिंगल यूज

केन्द्र सरकार के 12 वर्ष व राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर नगरपालिका ने चलाया पर्यावरण संरक्षण व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 12 में नगर पालिका परिषद द्वारा नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु डस्टबिन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही अपील की गयी कि वे गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग करके नगर पालिका के हवाले करें। अलग-अलग डस्टबिन में एकत्रित कूड़े को निर्धारित समय पर नगर पालिका के हवाले करने के लिये भी उन्हें प्रेरित किया। अधिशासी अधिकारी डा. मणि भूपण तिवारी ने नगरवासियों से अपील करते हुये कहा कि वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में नगर को उल्लेखनीय स्थान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। इस मौके पर सफाई एवं खाद्य निरीक्षण सत्य प्रकाश व राजीव कुमार, नगर पालिका की आई.ई.सी. टीम आदि लोग शामिल रहे।

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर एवं स्वाट/एसओजी/सिविलों की संयुक्त टीम ने पूर्वांचल एक्सप्रववे जम्हू अंडरपास के पास मु0अ0स0 072/2026, धारा 65(1), 123, भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 पाँसो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत निवासीगण कमालपुर बमनपुरा थाना मुहम्मदाबाद गौहना को गिरफ्तार किया। तपन्ती और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) और 61(2) (आपराधिक साजिश) की बढ़ोतरी की गई है अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय किया। प्रकाश में आये घटना में सलिल एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

संतों ने मूर्ति बरामदगी के लिए दिया ज्ञापन

बलिया, 12 जून (देवव्रत संवाद)। बलिया के सृष्णाली स्थित राम जानकी मंदिर से चोरी हुई मूर्तियों की बरामदगी को लेकर संतों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि मूर्तियाँ बरामद नहीं हुईं, तो संत समाज आमरण अनशन करेगा। यह पत्रक कमलानयन दास कृष्णा जी की ओर से दिया गया है। संतों ने बताया कि मंदिर से लड्डुगोपाल, राधाकृष्ण की युगल मूर्ति और हनुमान जी की मूर्तियाँ चोरी हुई हैं। इस संबंध में पांच सहोंने पहले थाना नगरा में प्रार्थनाओं दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में आठ चोरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, गिरफ्तारी के बावजूद आज तक मूर्तियाँ बरामद नहीं हो पाई हैं। संतों का आरोप है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर विवेचना समाप्त कर दी गई है और चांरजीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है। मूर्तियाँ बरामद न होने से पूजा-पाठ में बाधा आ रही है। संतों ने मांग की है कि थानाध्यक्ष नगरा और सीओ रसड़ा को तत्काल मूर्तियाँ बरामद करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे पूरे संत समाज के साथ डीएन कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी।

बलिया में 14 जून को प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा, 13 केंद्रों पर 5643 अभ्यर्थी होंगे शामिल

बलिया, 12 जून (देवव्रत संवाद)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा आयोजित प्रवक्ता (परुष/महिला) राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा के शांतिपूर्ण और सफल संचालन के लिए बलिया जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। इस संबंध में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि यह प्रारंभिक परीक्षा 14 जून को सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। जनपद में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 5643 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 13 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सहायक केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने परीक्षा केंद्रों का पूर्ण निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं

का सत्यापन सुनिश्चित करें। केंद्र व्यवस्थापकों को जनरेटर, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कर्मचारियों और पुलिस कांस्टेबलों की तैनाती समय पर करने को कहा गया। परीक्षा कक्षों में पंखों की व्यवस्था, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जोर दिया कि परीक्षा की गोपनीयता, पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसका उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराना है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सहायक केंद्र व्यवस्थापकों को तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने परीक्षा केंद्रों का पूर्ण निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं

खेलकूद पुलिस बल के जीवन का अभिन्न अंग-पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन में अंतरजनपदीय वाराणसी जोन बॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस लाइन में अंतरजनपदीय वाराणसी जोन बॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खेल भावना, आपसी समन्वय, शारीरिक दक्षता तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, धदोही, आजमगढ़, सोनभद्र जनपदों से आए खिलाड़ियों अस्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने उल्लेख खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों द्वारा रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिनमें खेल भावना, अनुशासन एवं टीम वर्क का उल्लेख उद्देश्य देखने को मिला।



प्रतियोगिता के दौरान पुलिस लाइन परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न टीमों के बीच हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन समन्वय, फुटी एवं खेल प्रतिभा का परिचय दिया, जिससे प्रतियोगिता अत्यंत रोमांचक एवं आकर्षक बन गई। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएँ पुलिस बल में आपसी सौहार्द एवं सहयोग

की भावना को मजबूत करती हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया तथा भविष्य में भी इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। उद्घाटन मैच जनपद-चंदौली व जनपद-मिजापुर के मध्य खेला गया जनपद-मिजापुर ने जनपद-चंदौली को 25-07, 25-07 से पराजित किया इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिभार निरीक्षक, विभिन्न जनपदों से आए टीम प्रभारी, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस लाइन में अंतरजनपदीय वाराणसी जोन बॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर एवं स्वाट/एसओजी/सिविलों की संयुक्त टीम ने पूर्वांचल एक्सप्रववे जम्हू अंडरपास के पास मु0अ0स0 072/2026, धारा 65(1), 123, भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 पाँसो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत निवासीगण कमालपुर बमनपुरा थाना मुहम्मदाबाद गौहना को गिरफ्तार किया। तपन्ती और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) और 61(2) (आपराधिक साजिश) की बढ़ोतरी की गई है अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय किया। प्रकाश में आये घटना में सलिल एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

संतों ने मूर्ति बरामदगी के लिए दिया ज्ञापन

बलिया, 12 जून (देवव्रत संवाद)। बलिया के सृष्णाली स्थित राम जानकी मंदिर से चोरी हुई मूर्तियों की बरामदगी को लेकर संतों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि मूर्तियाँ बरामद नहीं हुईं, तो संत समाज आमरण अनशन करेगा। यह पत्रक कमलानयन दास कृष्णा जी की ओर से दिया गया है। संतों ने बताया कि मंदिर से लड्डुगोपाल, राधाकृष्ण की युगल मूर्ति और हनुमान जी की मूर्तियाँ चोरी हुई हैं। इस संबंध में पांच सहोंने पहले थाना नगरा में प्रार्थनाओं दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में आठ चोरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, गिरफ्तारी के बावजूद आज तक मूर्तियाँ बरामद नहीं हो पाई हैं। संतों का आरोप है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर विवेचना समाप्त कर दी गई है और चांरजीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है। मूर्तियाँ बरामद न होने से पूजा-पाठ में बाधा आ रही है। संतों ने मांग की है कि थानाध्यक्ष नगरा और सीओ रसड़ा को तत्काल मूर्तियाँ बरामद करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे पूरे संत समाज के साथ डीएन कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी।

पुलिस लाइन में अंतरजनपदीय वाराणसी जोन बॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

मऊ, 12 जून (देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर एवं स्वाट/एसओजी/सिविलों की संयुक्त टीम ने पूर्वांचल एक्सप्रववे जम्हू अंडरपास के पास मु0अ0स0 072/2026, धारा 65(1), 123, भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 पाँसो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत निवासीगण कमालपुर बमनपुरा थाना मुहम्मदाबाद गौहना को गिरफ्तार किया। तपन्ती और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) और 61(2) (आपराधिक साजिश) की बढ़ोतरी की गई है अभियुक्त राकेश पुत्र नेहरू उर्फ अजीत को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय किया। प्रकाश में आये घटना में सलिल एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

संतों ने मूर्ति बरामदगी के लिए दिया ज्ञापन

बलिया, 12 जून (देवव्रत संवाद)। बलिया के सृष्णाली स्थित राम जानकी मंदिर से चोरी हुई मूर्तियों की बरामदगी को लेकर संतों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि मूर्तियाँ बरामद नहीं हुईं, तो संत समाज आमरण अनशन करेगा। यह पत्रक कमलानयन दास कृष्णा जी की ओर से दिया गया है। संतों ने बताया कि मंदिर से लड्डुगोपाल, राधाकृष्ण की युगल मूर्ति और हनुमान जी की मूर्तियाँ चोरी हुई हैं। इस संबंध में पांच सहोंने पहले थाना नगरा में प्रार्थनाओं दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में आठ चोरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, गिरफ्तारी के बावजूद आज तक मूर्तियाँ बरामद नहीं हो पाई हैं। संतों का आरोप है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर विवेचना समाप्त कर दी गई है और चांरजीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है। मूर्तियाँ बरामद न होने से पूजा-पाठ में बाधा आ रही है। संतों ने मांग की है कि थानाध्यक्ष नगरा और सीओ रसड़ा को तत्काल मूर्तियाँ बरामद करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे पू



सीएम योगी आज जनपद में करेंगे 955 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

आजमगढ़, 12 जून (देवव्रत संवाद)। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 13 जून को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पूर्वाह्न करीब 11.50 बजे हेलीकॉप्टर से विश्व विद्यालय परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहां वह सदर और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 955 करोड़ 40 लाख रुपये लागत की विकास परियोजनाओं की सोनात देंगे। इनमें विभिन्न विभागों की कुल 53 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 14 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 39 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। जानकारी के अनुसार लोकार्पण की जाने वाली 14 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 70 करोड़ 35 लाख रुपये है, जबकि 39 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिनकी

अनुमानित लागत 885 करोड़ 05 लाख रुपये है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यातायात मज और शाहगंज की ओर से आने वाले बड़े वाहनों को छतवारा चौराहा से डायवर्ट कर नरौली चौराहा, जामुरी, चंदेश्वर चौराहा और पकड़ी होते हुए उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। इसी प्रकार शहर की ओर से आने वाले बड़े वाहनों के लिए भी यही वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। गाजीपुर की ओर से आने वाले बड़े वाहन जामुरी चौराहा से डायवर्ट होकर नरौली चौराहा, पकड़ी और चंदेश्वर चौराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जामुरी चौराहा से छतवारा चौराहा होते हुए महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जाने वाले मार्ग पर बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि छोटे वाहनों, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस डायवर्जन व्यवस्था से छूट दी गई है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन कर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रबंधन और कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए यातायात पुलिस ने 13 जून को बड़े वाहनों के लिए अस्थायी रूट डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सुबह आठ बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस के अनुसार



विमला हत्याकांड में पांच आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर लगाया 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड

आजमगढ़, 12 जून (देवव्रत संवाद)। राजेंद्र, ससुर भोपाल और सास दुर्गावती की। उन्होंने कुल नौ गवाहों को न्यायालय आजमगढ़ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पांच आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस अर्थदंड की 80 फीसदी राशि मृतका के पिता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, निजामुद्दीन पट्टी निवासी मदन लाल की बेटी विमला का प्रेम संबंध गांव के हरेंद्र से था। सरायमीर थाने में पंचायत हुई, जिसके बाद 22 फरवरी 2015 को हरेंद्र और विमला का विवाह संपन्न हुआ। हालांकि, हरेंद्र के परिवार ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। वे विमला के मायके वालों से दहेज की मांग करने लगे। उन्होंने एक लाख रुपये और एक मोटर साइकिल की मांग की। दहेज की मांग पूरी न होने पर 14 मई 2017 को पति हरेंद्र, जेट कलेन्द्र, देवर



ने विमला को बुरी तरह पीटा। सूचना मिलने पर विमला के पिता ने उसे पहले संजूरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अगले दिन 15 मई को उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 25 मई 2017 को विमला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता और सहायक शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हरेंद्र, राजेंद्र, कलेन्द्र, भोपाल और दुर्गावती को दोषी ठहराया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने पांचों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस अर्थदंड की अरसी फीसदी राशि मृतका के पिता मदन लाल को दी जाएगी।

सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया

उपभोक्ताओं पर 150 करोड़ रुपये का भार

आजमगढ़, 12 जून (देवव्रत संवाद)। जिले में सरकारी विभागों पर 20 करोड़ रुपये से अधिक तथा उपभोक्ताओं पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया है। बकाया वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत निगम ने अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्व वसूली अभियान और ऑपरेशन जीरो थैफ्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। बकाया राशि जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 300 से 400 कनेक्शन विच्छेदित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में अब तक 72 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। निगम

का उद्देश्य क्षेत्र को बिजली चोरी से मुक्त बनाना है ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अधिशासी अभियंता ने कहा कि ओवरलोडिंग और कटिया कनेक्शनों के कारण ट्रांसफॉर्मरों एवं विद्युत प्रणाली पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने से फॉल्ट की घटनाएं भी अधिक हो रही हैं। स्थिति में सुधार के लिए अब तक 200 से अधिक ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन बिना अनुमति लोड बढ़ाने और अंधे कनेक्शनों के कारण समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बकाया वसूली और बिजली चोरी के विरुद्ध चल रहे दोनों अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



ग्रेट निकोबार परियोजना के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान शुरू

161 वर्ग किमी जंगल बचाने की मांग, राष्ट्रपति को भेजा जायेगा हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन

आजमगढ़, 12 जून (देवव्रत संवाद)। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित परियोजना के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने व्यापक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को एक उद्योगपति के हित में सौंपने का आरोप लगाते हुए परियोजना को पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा बताया। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आवास विकास तिराहा हारा की चुंगी पर अभियान का शुभारंभ किया गया। शहर अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से हस्ताक्षर कर पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान से जुड़ने की अपील की गई। काजी रियाजुल हसन ने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप देश की

महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित योजना के तहत 161 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों को उजाड़ने के साथ-साथ कथित कॉरपोरेट लूट को रोकना भी आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलकर प्रकृति और वन संपदा की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बद्ध-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मोहम्मद नजम शमीम, मोहम्मद आमिर, जावेद खान, बालचंद्र राम, मंत्र राज यादव, कैप्टन अशोक वर्मा, गोविंद शर्मा, सोनू प्रजापति, बृजेश पांडेय, फैज पलान, आरती महसूर बेग, फहीम खान, नदीम अहमद, नसीम अहमद, बिलाल आजमी, पंकज शर्मा, दानिश अहमद, रानू, राजा भाई सीकड़ी, राधे राम, राजू, जावेद अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

के साथ-साथ कथित कॉरपोरेट लूट को रोकना भी आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलकर प्रकृति और वन संपदा की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बद्ध-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मोहम्मद नजम शमीम, मोहम्मद आमिर, जावेद खान, बालचंद्र राम, मंत्र राज यादव, कैप्टन अशोक वर्मा, गोविंद शर्मा, सोनू प्रजापति, बृजेश पांडेय, फैज पलान, आरती महसूर बेग, फहीम खान, नदीम अहमद, नसीम अहमद, बिलाल आजमी, पंकज शर्मा, दानिश अहमद, रानू, राजा भाई सीकड़ी, राधे राम, राजू, जावेद अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।



प्रमारी मंत्री आज मुहब्बतपुर में लगाएंगे चौपाल

सतियांव, 12 जून (देवव्रत संवाद)। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन तथा समन्य विभाग के कैबिनेट मंत्री एवं आजमगढ़ जनपद के प्रमारी मंत्री अनिल राजगर शनिवार को मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुहब्बतपुर स्थित आदर्श अमृत संरोवर पर आयोजित चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रमारी मंत्री शाम छह बजे चौपाल लगाकर क्षेत्रीय लोगों से सीधे संवाद करके तथा उनकी शिकायतों और सुझावों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। प्रमारी मंत्री के आगमन एवं चौपाल कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को कार्यक्रम के तैयारी का जायजा लेने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्थल का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी

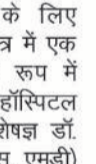
इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। खंड विकास अधिकारी हरिभद्र सिंह, एपीओ निरंज राय तथा ग्राम पंचायत अधिकारी धनंजय राय ने अमृत संरोवर परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को कार्यक्रम से पूर्व सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जानकारी के अनुसार प्रमारी मंत्री चौपाल कार्यक्रम के बाद अमृत संरोवर मुहब्बतपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है।



सबा हॉस्पिटल मुबारकपुर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. ए. अल्वी की सेवाएं शुरू

मुबारकपुर, 12 जून (देवव्रत संवाद)। क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मुबारकपुर स्थित सबा हॉस्पिटल में प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. ए. अल्वी (एमबीबीएस, एमडी) ने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। इससे पहले वे डॉ. शमीम डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी मरीजों को परामर्श देते रहे हैं। अब वे प्रतिदिन सबा हॉस्पिटल में बच्चों के मरीजों का परीक्षण एवं उपचार करेंगे। इस अवसर पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. शमीम अहमद ने बताया कि मुबारकपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से अनुभव्य बाल रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता को देखते

हुए अस्पताल परिवार में डॉ. ए. अल्वी को शामिल किया गया है, ताकि बच्चों को स्थानीय स्तर पर बेहतर एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने की सुविधा व्यवस्था के साथ-साथ एनआईसीयू की आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 24 घंटे आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे गंभीर स्थिति में बच्चों का तत्काल उपचार संभव हो सकेगा।



संभावित बाढ़ आपदा से निपटने को पीएसी व एसडीआरएफ ने किया तैयारियों का परीक्षण

मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है-डीजी पीएसी आलोक सिंह

आजमगढ़, 12 जून (देवव्रत संवाद)। मानसून के दौरान संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदेशभर में पीएसी और एसडीआरएफ की तैयारियों का परीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए) के दिशा-निर्देशों के तहत गुरुवार को 44 संवेदनशील जनपदों की 118 तहसीलों में राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक एक्सरसाइज-2026 का सफल आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक पीएसी आलोक सिंह के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास में पीएसी की 17 वाहिनियों से सात कंपनी और एक प्लाटून के साथ एसडीआरएफ की 16 टीमें ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कर्मिकों की क्षमता, उपकरणों की कार्यशीलता तथा आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करना था। अभ्यास के दौरान प्रशिक्षित जवानों ने नाव संचालन, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने, लाइफ जैकेट और अन्य जीवनरक्षक उपकरणों के उपयोग, रिसीवों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन तथा प्राथमिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया। साथ ही राहत एवं बचाव

कार्यों में प्रयुक्त आधुनिक उपकरणों की नियमित ब्रीफिंग की जाए तथा उपकरणों का



उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की भी जांच की गई। मॉक एक्सरसाइज में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन सेवा, एनडीआरएफ, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य संबंधित विभागों ने भी भाग लिया। इस दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और आपदा प्रबंधन की संयुक्त कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया गया। डीजी पीएसी आलोक सिंह ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ राहत दलों और एसडीआरएफ टीमों की समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मिकों की उपलब्धता बनाए रखी जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीएसी और एसडीआरएफ हमेशा जनसेवा के लिए तैयार रहेंगे और प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को तैयार हैं।

समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मिकों की उपलब्धता बनाए रखी जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीएसी और एसडीआरएफ हमेशा जनसेवा के लिए तैयार रहेंगे और प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को तैयार हैं।

दी टैक्स बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ

आजमगढ़, 12 जून (देवव्रत संवाद)। दी टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा शुक्रवार को होटल मानसरोवर, मडया (ठंडी साइड रोड) स्थित सभागार में सत्र 2026-27 के लिए चयनित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एवं संघ के दिग्गज वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय एखलाक अहमद के चित्र का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि रमेश प्रसाद जायसवाल ने संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा, मंत्री उमेश कुमार यादव

तथा कोषाध्यक्ष रमेश कुमार यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में शासन एवं बार काउंसिल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। विशिष्ट अतिथि प्रमोद्वेय राय ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज तिवारी, उपाध्यक्ष सूर्यभान पाल, सहमंत्री (जीएसटी) अभिषेक कुमार गुप्ता, सहमंत्री (आयकर) अनिल कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता तथा मीडिया प्रमारी प्रदीप कुमार गुप्ता को शपथ दिलाई। उन्होंने अधिवक्ता हितों के संरक्षण के लिए निरंतर सजग रहने का आह्वान किया।

91क और 91ख की भूमि के विवाद को लेकर उन्होंने 16 मई 2026 को शिकायत की थी। उनके अनुसार 31 मई को कानूनगो ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की थी और सभी पक्ष उस पैमाइश से संतुष्ट थे, लेकिन अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। उनका कहना है कि रिपोर्ट लंबित रहने से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। एक अन्य शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लेखपाल राजस्व संबंधी कार्यों और पैमाइश में मनामी करते हैं तथा बिना धन लिए कार्य नहीं करते। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में उपजिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार द्वारा जांच की कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, लंबित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कराने तथा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। साथ ही हल्का लेखपाल को ग्रामसभा गौरा से हटाकर किसी अन्य लेखपाल की तैनाती किए जाने की मांग भी की है।